महत्वपूर्ण एवं खास

इसलिए पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लाएंगे केंद्र, राज्य?

बेंगलुरु,(आरएनएस)। अगर आप वाहन मालिक हैं तो निकट भविष्य में पेट्रोल-डीजल के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में आने की उम्मीद न पालें। अभी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसकी जोरदार वकालत कर रहे हैं। पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाला टैक्स राज्य सरकारों और केंद्र का खजाना भरता है। ऐसे में दोनों सरकारें इन्हें जीएसटी के अंदर लाने की मांग अनसुनी ही करेंगी। अगर पेट्रोल-डीजल जीएसटी के तहत आ गया तो बेंगलुरु में इनकी कीमतें घटकर आधी रह जाएंगी। उदाहरण के तौर पर सोमवार को बेंगलुरु में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 71.62 रुपये थी, जो सबसे ऊंचे स्लैब के जीएसटी के तहत भी महज 44.06 रुपये होती। अगर इसे 12 प्रतिशत के जीएसटी स्लैब में रखा गया होता तो कीमत सिर्फ 38.49 रुपये प्रति लीटर होती। पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को जीएसटी के तहत लाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है क्योंकि जीएसटी काउंसिल इसे नई व्यवस्था में शामिल कर चुकी है, लेकिन टैक्स की सीमा तय नहीं की गई है। वैसे भी कर्नाटक सरकार किसी भी कीमत पर सोने का अंडा देनेवाले पेट्रोल-डीजल को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहेगी क्योंकि उसे प्रति माह औसतन 1,000 करोड़ रुपये की कमाई होती है। पेट्रोल पर 97.54 प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है जिसमें केंद्र सरकार की 67.54 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी और कर्नाटक सरकार का 30 प्रतिशत सेल्स टैक्स शामिल है। अगर इसे जीएसटी के तहत लाया गया तो केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल-डीजल से होने वाली आय 50 प्रतिशत कम हो जाएगी। नए जीएसटी सिस्टम के लागू होने के बाद पेट्रोल-डीजल पर एंट्री टैक्स खत्म होने से कर्नाटक सरकार को जुलाई में 200 करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशन के चेयरमैन एम प्रभाकर रेड्डी ने कहा, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने वाला प्रधान का प्रस्ताव बिल्कुल सही है क्योंकि ग्राहकों को इससे बहुत फायदा होगा। हमने भी केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल के सामने इस संबंध में अपनी बात रखी है। हालांकि ऐसा जान पड़ता है कि केंद्र और राज्य सरकारें यह होने नहीं देंगी क्योंकि कमाई के लिए वह पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और वे इसे बाधित नहीं करना चाहेंगी।

शेयर बाजार में बिकवाली हावी, निफ्टी 10100 के नीचे फिसला

नई दिल्ली,(आरएनएस)। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 10 बजे प्रमुख सेंसेक्स 168 अंक की गिरावट के साथ 32233 के स्तर पर और निफ्टी 57 अंक की गिरावट के साथ 10085 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कारोबार के दौरान निफ्टी 10100 के स्तर से नीचे फिसल गया। वहीं, छोटे और मझौले शेयर्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा बिकवाली मेटल शेयर्स में हो रही है। अमेरिकी फेडरल रिर्जव की ओर से ब्याज दरों को बरकरार रखने के फैसले के बाद गुरुवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार की मामूली बढ़त के साथ शुरुआत देखने को मिल रही है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 50 अंक की बढ़त के साथ 32450 के स्तर पर और निफ्टी 15 अंक की बढ़त के साथ 10153 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिडकैप में 0.19 फीसद और स्मॉलकैप में 0.24 फीसद की बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही फेडरल रिजर्व ने इस वर्ष एक और रेट हाइक के संकेत दिये हैं। फेड की बैठक के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। जापान का निक्केई 0.59 फीसद की बढ़त के साथ 20431 के स्तर पर, चीन का शांघाई 0.21 फीसद की बढ़त के साथ 3372 के स्तर पर, हैंगसैंग 0.09 फीसद की बढ़त के साथ 28153 के स्तर पर और कोरिया का कोस्पी 0.06 फीसद की कमजोरी के साथ 2410 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैठक साल के अंत तक रेट हाइक के संकेत के बाद बैंकिंग शेयर्स में तेजी से प्रमुख सूचकांक डाओ जोंस 0.19 फीसद की बढ़त के साथ 22412 के स्तर और एसएंडपी500 0.06 फीसद की बढ़त के साथ 2508 के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर बंद हुए हैं। नैस्डैक 0.08 फीसद की कमजोरी के साथ 6456 के स्तर पर कारोबार कर बंद हुआ है। सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो एफएमसीज और आईटी को छोड़ सभी सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं।

सहवाग पर अपनी टिप्पणी पर गांगुली ने दी सफाई

नई दिल्ली,(आरएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने शनिवार को वीरेंदर सहवाग पर की गई अपनी कथित टिप्पणी पर सफाई दी। पहले खबर आई थी कि गांगुली ने सहवाग की इस बात- बीसीसीआई में सेटिंग न होने की वजह से वह कोच नहीं बन पाए- पर नाराजगी जतायी थी। खबरों के अनुसार गांगुली ने सहवाग के इस कॉमेंट को मूर्खतापूर्ण करार दिया था। हालांकि गांगुली ने बाद में ट्विटर पर इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी। गांगुली ने कहा, सहवाग के बारे में पेश की गई मेरी टिप्पणी पूरी तरह गलत है। मैंने कहा था- सहवाग मेरा बहुत प्रिय है। मैं जल्द ही उससे बात करूंगा। सहवाग ने पहले कहा था कि वह बीसीसीआई में सेटिंग न होने की वजह से ही टीम इंडिया के मुख्य कोच नहीं बन पाए।

ह्युमन राइट्स का हवाला देकर रोहिंग्या को रिफ्यूजी बनाने की गलती न करें: राजनाथ

नई दिल्ली,(आरएनएस)। रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में रहने पर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि ह्युमन राइट्स का हवाला देकर अवैध शरणार्थियों को रिफ्यूजी बनाने की गलती नहीं की जानी चाहिए। वे म्यांमार से भारत में घुस आए हैं। रोहिंग्या रिफ्यूजी नहीं है, इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए। रिफ्यूजी स्टेटस लेने की एक प्रॉसेस होती है और इनमें से किसी ने इसे फॉलो नहीं किया है। रोहिंग्या मुस्लिमों को देश से बाहर करने का फैसला इंटरनेशनल लॉ का वॉयरेशन नहीं है, क्योंकि हमने 1951 के यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन नहीं किए थे। किसी भी रोहिंग्या ने भारत में शरणार्थी बनने के लिए अप्लाई भी नहीं किया है। बता दें कि देश में फिलहाल 40 हजार रोहिंग्या हैं। दावा है कि 16 हजार का यूएन

रिफ्यूजी डॉक्युमेंटेशन हो गया है।

ई-मंडियों में अब होगा सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से कारोबार: राधा मोहन

नई दिल्ली,(आरएनएस)। केंद्र सरकार किसानों की माली हालत में सुधार के लिए हर संभव प्रयास में जुट गई है। उपज के उचित व लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) को मजबूत बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। लेकिन इन ई-मंडियों की राह की सबसे बड़ी चुनौती इंटरनेट कनेक्टिविटी बन गई है। ज्यादातर राज्यों की मंडियों में यह बड़ी समस्या है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की बुलाई समीक्षा बैठक में ज्यादातर प्रतिनिधियों इसे गंभीर चुनौती करार दिया। रबी सीजन के तैयारी सम्मेलन में ही कृषि मंत्रालय की ओर से ई-नाम के कामकाज को लेकर सभी राज्यों को इस संबंध में स्पष्ट रूप से आगाह कर दिया गया है। इन ई-मंडियों में ऑनलाइन कारोबार ही करने की चेतावनी दी गई। 30 सितंबर के बाद किसी भी ई-मंडी में हाथों-हाथ होने वाले कारोबार और सौदों को कंप्यूटर में दर्ज करने की इजाजत नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक मंडियों के ई-कारोबार के सॉफ्टवेयर में भी इस तरह की तब्दीली कर दी गई है, ताकि कोई भी व्यापारी दूसरी तरह से होने वाले सौदों को ऑनलाइन नहीं बता सकता है। समीक्षा बैठक में ई-नाम के मामले में ज्यादातर राज्यों में प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को ई-मंडी के कामकाज पर बधाई दी गई। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्य ई-मंडियों की स्थापना और संचालन में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बैठक में चार राज्यों के कृषि मंत्रियों ने ही हिस्सा लिया। बाकी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कृषि मंत्री सिंह ने राज्यों में किसानों की जागरूकता के लिए अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया। बैठक के दौरान कुछ और समस्याएं उभर कर सामने आई। एक यह है कि ई-मंडियों में जिंसों के भाव किसानों के बजाय मंडी परिषद के लोग खोलते हैं। इससे किसानों की मर्जी के विपरीत भाव खुलते हैं, जिन्हें उन पर थोपा जाता है। समीक्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने अपनी ई-मंडियों में ऑनलाइन कारोबार करने वालों के शुल्क में रियायत देने की बात बताई। राजस्थान में ऐसे कारोबारियों के लिए पुरस्कार का प्रावधान किया है। कृषि मंडी सुधार के लिए मॉडल कानून के बारे में राधा मोहन ने राज्यों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में एकल बाजार (सिंगल मार्केट) बनेगा। यह किसानों और उपभोक्ताओं के हित में होगा। मॉडल कानून में मंडी शुल्क को सीमित किया गया है। इसके पहले जुलाई में हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वालों को चेतावनी जारी की थी।

भारतीय महिलाओं ने झटके 9 पदक, सोनिया को स्वर्ण

: कोमर्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग :

इस्ताबुल,(आरएनएस)। भारत की युवा महिला मुक्केबाजों ने अहमद कोमर्ट इंटरनेशनल मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में नौ पदक जीते हैं. रविवार (17 सितंबर) को समाप्त हुए इस टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज सोनिया ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया. सोनिया ने कजाखस्तान की झाजिरा उराकाबेवा को 48 किलोग्राम वर्ग में मात देकर 4-1 से स्वर्णिण जीत हासिल की. इसके अलावा, परवीन, अंकुशिता बोरो, शशि चोपड़ा और निहारिका गोनेला ने रजत पदक पर कब्जा जमाया. परवीन को फाइनल में रूस की अना-स्तासिया अरतामोनोवा से 54 किलोग्राम वर्ग में 2-3 से और शशि को भी फाइनल में कजा-खस्तान की व्ला-दिस्लावा कुख्ता से 57 किलोग्राम वर्ग में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा. अंकुशिता को 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में तुर्की की काग्ला अलुक ने और निहारिका को 75 किलोग्राम वर्ग में रूस की शामोनोवा अना-स्तासिया ने मात दी. भारतीय मुक्केबाज ज्योति (48 किलोग्राम), तिलोतामा चानू (60 किलोग्राम), मनीषा और ललिता ने 64 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता.

कोरिया ओपन के बाद जापान ओपन पर हैं सिंधू की निगाहें

तोक्यो,(आरएनएस)। हाल में कोरिया ओपन में चैंपियन बनी पी. वी. सिंधू बुधवार से यहां क्वॉलिफायर के साथ शुरू होने वाले 3,25,000 डॉलर इनामी राशि के जापान ओपन में तीसरा सुपर सीरीज खिताब अपने नाम करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा किदांबी श्रीकांत और साइना नेहवाल भी इसमें भाग लेंगे। सिंधू ने पिछले हफ्ते कोरिया ओपन में मिनात्सु मितानी के खिलाफ दूसरा गेम गंवाने के बाद जीत दर्ज की थी और अब वह फिर इस हफ्ते शुरुआती दौर में जापानी खिलाड़ी से भिड़ेंगी।

दीपिका के साथ प्रोमिला व मोनिका तीरंदाजी विश्व कप टीम में

जमशेदपुर,(आरएनएस)। मेक्सिको में अगले महीने होने वाली विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए दीपिका कुमारी, प्रोमिला दायमुरी और मोनिका सोरेन ने अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं, पुरुष वर्ग में तरुणदीप राय, अतनु दास और मंगल सिंह चंपिया को टीम में शामिल किया गया है। विश्व कप तीरंदाजी के लिए चयन ट्रायल में पुरुष व महिला वर्ग में शीर्ष आठ-आठ खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। महिला वर्ग में प्रोमिला, दीपिका, मोनिका, बोंबयाला देवी, लक्ष्मी रानी माझी, प्राची सिंह, वी शारदा व एन लावण्या को चयन ट्रायल में भाग लेने का मौका मिला था।वहीं, पुरुष वर्ग में तरुणदीप, अतनु, चंपिया, राहुल बनर्जी, गौतम सिंह, विश्वास, सुखचैन, सचिन गुप्ता शामिल थे। टाटा स्टील के जयंत तालुकदार को लेकर अंतिम समय तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही। साइ, कोलकाता में चयन ट्रायल के दौरान जयंत ने स्कोरशीट पर साइन नहीं किया था, जो कि जरूरी होता है। हालांकि नियम के अनुसार खिलाड़ी के पीछे ज्यूरी होना चाहिए और अंतिम राउंड के पहले यह घोषणा करनी होती है कि सभी खिलाड़ी स्कोरशीट पर हस्ताक्षर करें। नतीजा, दूसरे राउंड के स्कोरशीट पर जयंत हस्ताक्षर करना भूल गए। इसके कारण तीरंदाजी फेडरेशन ने उन्हें ट्रायल में शामिल करने से इन्कार कर दिया।

हरफनमौला हार्दिक पंड्या चेन्नई वनडे में शानदार प्रदर्शन के बावजूद इस कारण किए गए ट्रोल

नई दिल्ली,(आरएनएस)। ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार के मैच में टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. हार्दिक ने पहले बल्लेबाजी में दम दिखाते हुए पांच चौकों और इतने की छक्कों की मदद से 83 रन बनाए और फिर मेहमान टीम के दो बल्लेबाजों को भी आउट किया. इस दोहरे प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया. हालांकि इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद पंड्या को सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस की ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा. दरअसल हार्दिक ने मैच में बल्लेबाजी के दौरान आईपीएल (आईपीएल)की अपनी टीम मुंबई इंडियंस के ग्लव्ज पहन रखे थे. क्रिकेटप्रेमियों को यह बात पसंद नहीं आई कि पंड्या ने टीम इंडिया की ओर से इंटरनेशनल मैच खेलते हुए मुंबई इंडियंस टीम के ग्लव्ज का उपयोग किया. आईपीएल की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके)ने एक ट्वीट कर पंड्या के मुंबई इंडियंस के ग्लव्ज पहनकर खेलने की पुष्टि की थी. सीएसके के इस ट्वीट में कहा गया, पंड्या मुंबई इंडियंस (एमआई) के ग्लव्ज पहने. एमएस धोनी की चेपक (चेन्नई का

स्टेडियम) पर वापसी. दोनों बीसीसीआई के लिए खेल रहे हैं. अनेकता में एकता. ञ्चआईपीएलजीत के लिए. इस ट्वीट के बाद पंड्या की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई. तबरेज शेख नाम के एक यूजर ने लिखा, पंड्या ने मुंबई इंडियंस के स्लोगन के साथ न्याय किया, दिल से इंडियन, मुंबई इंडियन. भारत के लिए खेलते हुए वे एमआई के बैटिंग ग्लव्ज पहनकर खेले. एक अन्य ट्विटर हैंडल से लिखा गया, कोई कारण, भारतीय टीम के लिए खेलते हुए हादिक पंड्या ने अपनी फ्रेंचाइजी की टीम के ग्लव्ज क्यों पहने. एक अन्य यूजर ने लिखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कुंगफू पंड्या में जादू है या मुंबई इंडियंस के ग्लव्ज में या फिर कैरेबियन हेयरस्टाइल में. अपनी 83 रन की पारी के दौरान हार्दिक ने एडम जंपा की लगातार तीन गेंदों पर छक्के उड़ाए. इस ओवर में कुल 24 रन बने.उनकी पारी में पांच चौके और इतने ही छक्के शामिल थे.

सहवाग की 'सेटिंग' टिप्पणी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए: ठाकुर

लुधियाना,(आरएनएस)। बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरेंद्र सहवाग के इस बयान को अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि बीसीसीआई के पदाधिकारियों से संरक्षण नहीं मिलने के कारण वह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद की दौड़ में चूक गए। कोच के पद के लिए कोई 'सेटिंग' नहीं थी, सहवाग के इस बयान के संदर्भ में एक

समारोह के इतर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी सांसद ठाकुर ने कहा,इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। सहवाग भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद की दौड़ में रवि शास्त्री से पिछड़ गए थे।

शोर नहीं मचाएं, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाएं विपक्षी दल वाले राज्य : जेटली

नई दिल्ली,(आरएनएस)। केंद्र और राज्यों में राजस्व संग्रह की स्थिति के मद्देनजर पेट्रोल उत्पादों पर लगने वाले शुल्कों में कमी की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इस मामले में राजनीति भी बढ़ती जा रही है। अपने दस वर्ष के शासन में पेट्रोल उत्पादों पर टैक्स नहीं घटाने वाली कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि वह शुल्कों में कटौती कर जनता को राहत दे। इस पर आईना दिखाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विपक्ष को अपनी सरकारों वाले राज्यों में वैट घटा कर पेट्रोल-डीजल मूल्यों में कमी की शुरुआत करनी चाहिए। या फिर कहना चाहिए कि उन्हें इस बाबत जुटाए गए टैक्स में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। जेटली ने अपनी तरफ से केंद्रीय शुल्कों में कटौती के कोई संकेत नहीं दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को तमाम समाजिक और ढांचागत परियोजनाओं के लिए सरकार को पैसे चाहिए। यह धन उसके पास राजस्व संग्रह के जरिये ही आता है। यही नहीं सरकार जो राजस्व हासिल करती है, उसका 42 फीसद भी राज्यों के हिस्से जाता है। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राज्यों के लिए वैट को घटाना असंभव है। राज्यों की वित्तीय

स्थिति अच्छी नहीं है। चालू वर्ष की बात करें तो पहली तिमाही में राज्यों ने 43,404 करोड़ रुपये का शुल्क पेट्रोलियम उत्पादों से एकत्र किया है। केंद्र ने मौजूद वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 1,24,508 करोड़ रुपये का कुल संग्रह किया है। वर्ष 2014-15 में पेट्रो उत्पादों से केंद्र सरकार का कुल राजस्व संग्रह 3,32,620 करोड़ रुपये का था। यह पिछले वित्त वर्ष में बढ़ कर 5,24,304 करोड़ रुपये का हो गया। जुलाई में भारत ने औसतन 47.86 डॉलर प्रति बैरल की दर से क्रूड खरीदा। अगस्त में यह दर 50.63 डॉलर हो गई। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में जुलाई से 7.44 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। अमेरिका में तूफान आने से चालू महीने में क्रूड और महंगा हुआ है। अक्टूबर से सर्दियों की मांग निकलने से कच्चा तेल और भड़क सकता है। तेल निर्यातक देशों ने साफ संकेत दिए हैं कि वे क्रूड उत्पादन में और कटौती करेंगे ताकि इसकी कीमत को मौजूदा स्तर पर बनाए रखा जा सके।

कंपनियों को जमा करना पड़ सकता है पहली छमाही में आय का अनुमान

नई दिल्ली,(आरएनएस)। कंपनियों व करदाताओं को अप्रैल से सितंबर तक के आय का अनुमान और टैक्स देनदारी की जानकारी आयकर विभाग के पास जमा करानी पड़ सकती है। यह उन कंपनियों व करदाताओं पर लागू होगा, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना है। इसके लिए 15 नवंबर की तारीख तय की जा सकती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आय और एडवांस टैक्स की जानकारी देने के लिए फॉर्म 28एए भरने पर संबद्ध पक्षों से राय मांगी गई है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले एडवांस टैक्स में कमी होने की स्थिति में कंपनियों को उसका कारण भी बताना पड़ेगा। इस जानकारी से आयकर विभाग को किसी कंपनी के आमदनी के रुझान को समझने में मदद मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले कुल आय में पांच लाख रुपये या 10 फीसद (जो अधिक हो) से ज्यादा की कमी होने पर करदाताओं को अप्रैल से दिसंबर की जानकारी 31 जनवरी तक देनी होगी। अभी करदाताओं को पूरे वित्त वर्ष के आयकर पर एडवांस टैक्स सीबीडीटी के पास जमा कराना होता है। यह चार किस्तों में 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को जमा कराया जाता है। उन्हें अनुमानित आय की जानकारी नहीं देनी होती।

शेल कंपनियों पर सरकार ने बढ़ाई सख्ती

नई दिल्ली,(आरएनएस)। केंद्र सरकार ने मुखौटा कंपनियों और उनके संचालकों पर सख्ती बढ़ा दी है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने ऐसी कंपनियों के 55 हजार से ज्यादा डायरेक्टरों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया, ताकि इन लोगों को फिर किसी कंपनी में इसी तरह की भूमिका नहीं मिल सके। सरकार ने ऐसी मुखौटा कंपनियों को चिह्नित किया है, जिन्होंने कोई कारोबारी गतिविधि नहीं की है, या जिनका लगातार तीन साल से वार्षिक रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जमा कराया गया है। इन कंपनियों से जुड़े 1.06 लाख से ज्यादा डायरेक्टरों की पहचान भी की गई है। निकट भविष्य में बाकी निदेशकों के नाम भी उजागर किए जा सकते हैं। विभिन्न कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास पंजीकृत दो लाख से ज्यादा ऐसी कंपनियों का पंजीकरण रद किया जा चुका है। आरओसी द्वारा जारी की गई जनसूचनाओं के अनुसार अब तक चेन्नई की 24 हजार से ज्यादा ऐसी कंपनियों से जुड़े लोगों का नाम सार्वजनिक किया गया है। इसी प्रकार अहमदाबाद और एर्नाकुलम में 12-12 हजार से ज्यादा कंपनियों से जुड़े निदेशकों के नाम उजागर किए गए हैं। इनके अतिरिक्त कटक, गोवा और शिलांग के आरओसी की ओर से भी डायरेक्टरों की सूची सार्वजनिक की गई है। दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ के आरओसी ने अब तक सूची प्रकाशित नहीं की है। माना जा रहा है कि इनमें से कई नाम बड़े राजनीतिक और कॉरपोरेट घरानों से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में इसलिए निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।